राजस्थान का उद्योगीकरण

203. **डा. अबरार अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान के उद्योगीकरण के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में राजस्थान में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उन उद्योगपतियों को, जो राजस्थान में ऐसे उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई सहायता या अनुदान देने का विचार रखती है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश की तुलना में राजस्थान में छोटे और बड़े उद्योगों में कुल कितने प्रतिशत पूंजी का निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित की गयी नयी औद्योगिक नीति के अधीन 18 उद्योगों की एक छोटी सी सूची के अलावा कोई भी परियोजना स्थापित करने के लिए अब औद्योगिक लाइसेंसीकरण की आवश्यकता नहीं है । स्थापना स्थल संबंधी सरकारी नीति के अनुसार उद्यमी अपने एकक की स्थापनार्थ कोई भी स्थान चुन सकता है ।

जहां तक केन्द्र सरकार के उपक्रमों की परियोजनाओं का प्रश्न है, ऐसी परियोजनाओं के स्थापना स्थल का चयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तकनीकी-आर्थिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है ।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के एककों का पंजीकरण जिला स्तर पर किया जाता है । संगठित क्षेत्र के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान समूचे देश में और राजस्थान में औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु जारी किये गये आशय पत्रों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	समूचे देश के लिए जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या	राजस्थान के लिए जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या
1989	1182	28
1990	825	23
1991 (अक्तूबर तक)	594	21

इन तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये आशय पत्रों पर समग्र देश में पूर्वानुमानित निवेश की कुल राशि 48228.27 करोड़ रुपये थी जिसमें राजस्थान में स्थापित होने वाले एककों में अनुमानित निवेश 1460.85 करोड़ रुपये था जो कुल राशि का 3.02 प्रतिशत बैठता है ।

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, यह एक बड़ी विडबना है कि देश की अर्थव्यवस्था के एके बड़े हिस्से को नियंत्रित करने वाले उद्योगपतियों का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में है और

राजस्थान ही उद्योग में पिछड़ा हुआ है । यह बड़ी ही विडंबना की बात है ।

सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था, अगर आप मेरे प्रश्न के "क" और "ख" भाग को देखें तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही स्पष्ट और स्पैसिफिक थे, लेकिन जो उत्तर मिला, उससे राजस्थान के संबंध में "क" और "ख" भाग के लिए कोई स्पैसिफिक उत्तर नहीं है । मैंने पूछा था कि क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है राजस्थान के संबंध में "क" पार्ट और "ख" पार्ट में मैंने पूछा था कि सरकार निकट भविष्य में राजस्थान में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ? लेकिन, इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला और जो उत्तर मिला उसके अंदर नई औद्योगिक नीति की बात की गई है । उसमें बातें कही गई है, एक तो औद्योगिक लाइसेंसीकरण की आवश्यकता अब किसी को भी नहीं है और दूसरी बात यह कही गई है कि उद्यमी अपनी सुविधा से स्थान का चयन कर सकता है

तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि हमारी नीति उद्योग के अंदर विकेन्द्रीयकरण की हमेशा रही है । और जब से इस पालीसी के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हैं । 18 उद्योगों को छोड़कर, और उद्यमी अपनी इच्छा से स्थान का चयन कर सकता है तो केन्द्रीयकरण को कैसे आप रोक पाएंगे ? इसके आधार पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण होगा, जबकि हमारी नीति विकेन्द्रीयकरण की है कि छोटी-छोटी जगहों में, पिछड़ी जगहों में जाएं । तो माननीय मंत्री जी इसको कैसे पूरा करेंगे ? और, मेरा सप्लीमेंटरी का "ख" पार्ट यह है कि जो सूचना राजस्थान के बारे में, समचे देश के बारे में जारी किए गए आशय-पत्रों के बारे में दी है, उससे स्पष्ट है कि वर्ष 1989 में 1182 में से 28 आशय पत्र राजस्थान के लिए किए गए हैं तो इस आधार पर राजस्थान की स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं । राजस्थान में जिन 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस देते हैं उनमें से किसी उद्योग के संबंध में कोई योजना विचाराधीन है ? उसमें क्या कोई एन० आर० आईज भी है और उन एन० आर० आईज० को प्रोत्साहित करने की कोई बात आप वहां कर रहे है ?

SHRI P. J. KURIEN: Sir, the hon. Member's contention that the question has not been properly answered, is not correct. Sir, the first thing is, because we have brought in liberalisation in the new Industrial Policy, it is not possible for the Government to decide the location of a particular industry. Now the decision is taken on techno-economic consideration and on commercial viability by the industrialists themselves. Therefore, we cannot ask a particular industry to go to a particular place. That is why, in the answer itself I said, under the new Industrial Policy, the requirement of industrial licensing has been abolished and the Government cannot direct them now. But, however, the same Policy has taken certain precautions to see that the industry is not concentrated in cities and certain areas. For one thing we have got the locational restrictions.

Secondly, the Government also have announced a scheme of 'growth centres' which is aimed at taking industry to backward areas and far-flung areas where infrastructural facilities are available. The Government have announced 70 growth centres for the 8th Five Year Plan and four of them have already been identified in Rajasthan also.

With regard to public sector undertakings, again the decision to set-up an industry in the public sector is to be taken by the administrative Ministry and that again is on techno-economic considerations and it is not possible for the Government to allot an industry to a particular State. But if there is scope for new industries in Rajasthan and if applications are forthcoming, the Government will certainly consider them favourably.

With regard to the 18 industries which have been included for licensing, I can assure the hon. Member that if any application is coming from industrialists in Rajasthan or from anywhere to set up an industry in Rajasthan, the Government will certainly consider if favourably, subject to viability and techno-economic considerations.

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, अपने पहले सप्लीमेंटरी में एक तो एन० आर०आई०० के संबंध में मैंने बात पूछी थी कि क्या राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के संबंध में कुछ एन०आर०आई०० भी है ? इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया और केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण के संबंध में.... (व्यवधान)...

SHRI P. J. KURIEN: Yes Sir. With regard to NRIs, the Government of India has already announced a scheme for encouraging NRIs to invest in industry, especially in high priority areas. Not only that, NRIs are allowed 100 per cent equity in any industry.

MR. CHAIRMAN: He wants to know about Rajasthan.

SHRI P. J. KURIEN: I am coming to that. Sir. But with regard to Rajasthan, again, Sir, it is for somebody to apply. If any NRIs application is coming for Rajasthan, certainly we will consider that sympathetically and try to clear the same. That much assurance I can give.

With regard to dispersal of industry, I have already said, we have a scheme of growth centres which we are going to implement earnestly.

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, हमारे देश में और राजस्थान में अभी तक कुछ नो इन्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट निर्धारित थे, जहां कोई भी उद्योग नहीं था । ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की एक सूची उद्योग मंत्रालय के अंदर बनी हुई थी । उन जिलों को कई प्रकार से प्रोत्साहन, मदद, सहायता, सबसिडी दी जाती थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब उन नो इन्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होगा ? क्या उन पिछड़े हुए जिलों को अब भी वह मदद जारी रखेंगे या किसी प्रकार से उन पिछड़े जिलों को आगे लाने के लिए वे इस औद्योगिक नीति या उनकी नई पालिसी में कुछ सुधार कर रहे हैं ?

मैंने सप्लीमेंटरी का (ख) भाग है कि राजस्थान में कौन-कौन से बड़े उद्योग इस समय बंद पड़े हैं और उनको चालू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? इस संबंध में सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी, जो चार सालों से बंद पड़ी है और वहां के मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन दिलवाने के लिए और उसको चालू करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? क्या आप डी०आई०एफ०आर० को यह निर्देश देंगे कि वह तत्काल इस संबंध में निर्णय लें ताकि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिले और उन्हें उनका बकाया वेतन मिले ।

SHRI P. J. KURIEN: Sir, with regard to subsidy given to "no industry district", as early as in 1988 itself, the subsidy has been done away with.

MR. CHAIRMAN: Has it been discontinued?

SHRI P. J. KURIEN: Yes, Sir the reason being that these subsidies were used by individuals and in many cases we have found that they were not encouraging the growth of industry. Therefore, the Government thought that it would be in the best interest of the country and industry to promote infrastructural facilities. That is why in place of Subsidy Scheme the Government has introduced the Growth Centre Scheme. Under the Growth Centre Scheme, we will select centres, especially

in backward areas where the Government will provide all infrastructural facilities. The Government will provide telecommunication or banking facilities for attracting industries. On one growth centre it is intended to spend about Rs. 25 crores or Rs. 30 crores. Obviously Rs. 10 crores is from the Government of India and partially the State Governments will contribute Banks and other financial institutions will also contribute. These Growth Centres will act as an attracting point for industries in those areas. These Growth Centre Schemes are now implemented in place of investment subsidy which was available to backward as well as no-industry districts.

MR. CHAIRMAN: What about Sawai Madhopur? He is interested in the closed Swawai Madhopur Cement Industry.

SHRI P. J. KURIEN: As the hon. Member has mentioned, the Industry is closed now. However, such closed industries... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: He wants you to expedite it.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, if you direct me, we will do whatever is directed.

MR. CHAIRMAN: No, no, I am not directing. I don't direct at all. He wants to know whether you will expedite it. My job is only to summarise the questions, long questions, and I try to quote them in one sentence.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, with regard to cement industries, sick industries, we have refer the matter to BIFR and it is for BIFR... (*Interruption*)...

MR. CHAIRMAN: He wants to know about this particular industry. If you don't know about it, you can communicate it to him later on.

SHRI P. J. KURIEN: All right, Sir. With regard to this specific case, I will apprise the hon. Member later on.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, it is a very important question and I want to specifically know from the hon. Minister... (*Interruption*)...

MR. CHAIRMAN: He has directed it to the Minister and to you also. ...(*Interruption*)... नहीं-नहीं सवाल माधोपुर का नहीं है, राजस्थान के लोग बाहर इंडस्ट्री डालते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं डाल रहे हैं ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : कमल बम्बई में रहते हैं और राजस्थान की बात करते हैं।

श्री सभापति : वह राजस्थानी होने से इंकार नहीं कर सकते।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : सवाई माधोपुर के डायरेक्टर हैं ये।

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, I want to know from the hon. Minister that in view of the new Industrial Policy what the instruments available with the Government are to ensure that industries go into backward areas and how the Government proposes to ensure the growth of backward areas not only in Rajasthan but also in other States. This question relates to Rajasthan. Please tell us how you are going to ensure that industrial growth takes place in the backward areas since only 18 industries are licensed now. All other industries are delicensed. So entrepreneurs are free to go wherever they want and most entrepreneurs—excuse me—like to go to more developed areas like Bombay and Delhi. I want to know what the instrumentalities available with the Government are to ensure the development of backward areas; what the Government proposes to do to ensure that the industries go there because employment is the main thing and the main growth rate is that

employment growth rate which is going down. I want to know what the Government is doing.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, I would like to submit that there need not be any apprehension that under the new Industrial Policy industries will not go to the backward areas because today the decision is taken by the investor on economic consideration, on commercial viability, and wherever raw-material is available, industry has to go there. Before the announcement of this new Industrial Policy... *(Interruption)*...

SHRI JAGESH DESAI: There is no infrastructure at all there... *(Interruptions)*...

SHRI P. J. KURIEN: Please listen to me... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is this? *(Interruptions)*

SHRI P. J. KURIEN: Please listen to me. Before the Industrial Policy a decision was taken by the Government as to at which place the industries should go. However, you admit that there are a lot of industries which are still backward. Because today commercial viability is the most important consideration, industries have to go to the backward areas where raw-material is available. No. two, it is the responsibility of the State Government to provide infrastructural facilities. Sir, infrastructure is the most important aspect. Industries are being attracted to backward areas where infrastructural facilities are there. (1) State Governments are giving infrastructural facilities and incentives. (2) Central Government has already announced the Growth Centres Scheme which is mainly aimed at attracting industries to backward areas. We have already announced 70 Growth Centres in backward areas in the Eighth Plan. We may increase the number also. Our long-term plan is that these Growth Centres will be in backward areas wherever possible.

MR. CHAIRMAN: Are you taking up any of them now?

SHRI P. J. KURIEN: Yes, Sir. Seventy Growth Centres have been taken up in the Eighth Plan and in Rajasthan five have been allotted and the Government's idea is to have more Growth Centres so that backward areas are provided with all infrastructural facilities and naturally industries will be attracted to such areas where infrastructural facilities are there.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, he has not answered my question. Let me ask the Government whether they will instruct financial institutions to give priority to backward areas rather than other projects. If there are two applications, one from a backward area and the other from Bombay, they will see which is commercially viable. Sir, you know what commercial viability is. Entrepreneurs like to go where there is a market,—where there are facilities. Nobody will go to Rajasthan or Bihar.

SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Sir, the investment of Government of India in Rajasthan is less than 2 per cent of the total public sector investments in the country. Rajasthan accounts for 10.4 per cent area of the country and 5 per cent of the population of the country. Looking to that, the investment of Government of India in public sector units in Rajasthan is very low, very poor. With the trend towards privatisation and encouragement by the Government of India to private sector, chances of new public sector units coming to Rajasthan are very remote. However, there are two areas where the Government can play an important role and assist in the development of industries in Rajasthan. These are expansion of existing public sector units and exploration of oil in new areas. My questions, therefore, are: (a) Is the Government prepared to increase investments in the existing public sector projects so as to provide more employment and augment industrialisation of Rajasthan? (b) Is the Government of India or ONGC prepared to do exploratory drilling in more areas in the State such as Kishangarh shelf, Shahgarh depression, Sanchor-Barmer basin and Bikaner Nagur basin?

SHRI P. J. KURIEN: Sir, with regard to the hon. Member's second part of the question, I submit that it should be addressed to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. However, I will report it to the concerned Ministry and I will request them to give a reply. With regard to the first part of the question regarding more investment in public sector units in Rajasthan, I can assure the hon. Member that subject to other things being equal backward areas will be given preference in investment in public sector undertakings.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, जो नई औद्योगिक नीति है उसका जहां एक तरफ सब ने स्वागत किया है क्योंकि उसमें कई बड़े अच्छे पहलू हैं किन्तु जो पहलू सन्देह और भय उत्पन्न करते हैं जिनके विषय में पूर्व में पूरक प्रश्न पूछ गए, मैं उस पर एक स्पैसिफिक प्रश्न पूछकर उत्तर जानना चाहूंगा। जो आपने कहा कि 70 ग्रोथ सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप यह सोचते हैं कि ये उद्योग पिछड़े इलाकों में भी आएंगे उन 70 ग्रोथ सेंटर्स में से कितने आदिवासी इलाकों में स्थापित किए हैं और कितने पहाड़ी इलाकों में स्थापित किए हैं और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए जिले थे जिनको "नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट" के रूप में जाने जाते हैं उनमें से कितने ग्रोथ सेंटर खोले गए हैं जिससे हम कंविंस हो सकें कि आप इन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से पिछड़े जिलों का औद्योगीकरण कर रहे हैं अन्यथा यह साफ हो जाएगा कि ऐसी जगह आप इनको लगा रहे हैं जहां पहले से ही इंडस्ट्रीज हैं।

MR. CHAIRMAN: He wants to know about the allocation of growth centres.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, I have already suggested that there are certain growth centres.... (*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: He wants to know how many of them are in the tribal areas, how many are in the hilly areas and how many of them are in otherwise "No industry" areas.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, I will need a separate notice for that.

MR. CHAIRMAN: Will you supply it?

SHRI P. J. KURIEN: Yes, Sir.

SHRI AJIT P. K. JOGI: My question relates to Rajasthan. You could tell us about Rajasthan.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, in Rajasthan we have allotted five growth centres.

MR. CHAIRMAN: Where are they?

SHRI P. J. KURIEN: Sir, out of these five growth centres, four have been identified. The identification is done in concurrence with the State Governments. The State Government recommends and we select. The four centres that have so far been identified are Abu Road Bhilwara, Bikaner and Jalawa. The fifth one has to be identified. We are waiting for the recommendation of the State Government However, I would like to add that selection of the growth centres is made on the recommendation of the State Government. We give guidelines to the State Government. We give guidelines to the State Governments and on their recommendation and also with their concurrence, final selection is made... (*Interruptions*)....

SHRI AJIT P. K. JOGI: The political element will creep in if you go by the recommendation of the State Government.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 204

Documentaries on Sankardeva and Jyoti Prasad Agarwala

*204. DR. NAGEN SAIKIA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have cleared the proposals for documentaries on Sankaradeva and Jyoti Prasad Agarwala;

(b) if so, when these were cleared;

(c) if not, the reasons therefor; and